>

Title : Need to check corruption and irregularities in implementation of Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme in the country.

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): सभापति महोदया, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ग्रामीण गारंटी योजना को लगभग पांच साल पूरे हो चुके हैं। इन पांच वर्षों की कालावधि को देखा जाए तो मनरेगा का बहुत अच्छा चित्र हमारे सामने नहीं आता। जिस उद्देश्य के लिए लिए मनरेगा योजना बनाई गई थी, वह यह था कि ग्रामीण भारत में निवास कर रहे नागरिकों को कम से कम प्रतिवर्ष सौ दिन का रोजगार मुहैया हो, इसी उद्देश्य को सामने रखकर 2006 में यह योजना कार्यान्वित की गई थी और इसके लिए चालीस हजार करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया था। किन्तु भ्रष्टाचार ने इस योजना पर पानी फेर दिया। यह मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि मनरेगा के तहत जो काम हुए उनकी गुणवत्ता नहीं के बराबर है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 12 करोड़ जॉब काड्र्स का वितरण हुआ है और दस करोड़ बैंक खाते खोले गये हैं।[B8] किंतु जो सपना हमने देखा था कि मनरेगा के कारण गांवों की तस्वीर बदल जाएगी, वैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बल्कि हम सौ दिन का रोजगार देने में भी असफल रहे हैं। औसत रोजगार 50 दिन से भी कम है। लेकिन कुछ राज्यों में मनरेगा का रिकार्ड अच्छा है।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह काम बराबर होते रहना चाहिए ताकि लोगों को इससे फायदा पहुंचे।